

राजस्थान सरकार
सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय, झुंझुनू

गिरते जल स्तर को बचाने में सभी की भागीदारी जरूरी

- गुप्ता

झुंझुनू, 29 जून: जिला कलेक्टर आलोक गुप्ता ने कहा है कि जिले में गिरते जल स्तर को बचाने में सभी की भागीदारी जरूरी है। जब तक हम जल संरक्षण के महत्व को नहीं समझेंगे, तब तक इस दिशा में आम व्यक्ति को जागरूक करके आने वाली पीढ़ी के लिए पानी नहीं बचा पाएंगे। वे मंगलवार को यहां सूचना केन्द्र के सभागार में राज्य जल संसाधन आयोजना विभाग एवं सिंचाई विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित संशोधित जल नीति की एक दिवसीय कार्यशाला में बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि हर साल गिरते जल स्तर के कारण दिन प्रतिदिन पानी की समस्या बढ़ रही है। यह समस्या हमें अभी से आने वाले जल संकट की ओर इंगित कर रही है। कहीं ऐसा नहीं हो कि भविष्य में हमारी पीढ़ियों को पानी के लिए जुझना पड़े। हमें अभी से चिन्तन और मनन करके पानी बचाने के लिए गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले पानी के लिए जो तालाब, कुए, बावड़ी बनाए जाते थे आज उनका महत्व बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि सभी के समन्वित सहयोग से गिरते जल स्तर की समस्या का निराकरण हो सकेगा। आज की कार्यशाला में ऐसे सुझावों के आधार पर प्रस्ताव बनाए जाएं जो राज्य सरकार को भिजवाए जा सकें।

उप जिला प्रमुख विद्याधर सिंह गिल ने भी गिरते जल स्तर पर चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा कि जल चेतना जागृत करने के लिए अभियान के रूप में जल नीति के बारे में आमजन को बताना होगा। पानी की बूंद-बूंद के बचाव के लिए हमें नहाने, धोने, बरतन आदि साफ करने तथा खेती में कम पानी में अच्छी पैदावार देने वाली फसलों की बुवाई करनी होगी। जल संरक्षण के लिए राष्ट्रीय जल नीति बनाई जानी चाहिए और पानी के दुरुपयोग को रोककर पानी के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने सभी को तन-मन से संशोधित जल नीति के क्रियान्वयन में भागीदारी दर्ज करवाने का आह्वान किया।

नगर परिषद के सभापति खालिद हुसैन ने अपने उद्बोधन में कहा कि जल ही जीवन है, जल है तो कल है, रहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, बिजली बचाओ पानी बचाओ जैसे श्लोगन का उल्लेख करते हुए कहा कि अगर जल के अधिक दोहन को रोका नहीं गया तो धरती का जल कम हो जाएगा। उन्होंने बताया कि नगरीय क्षेत्रों में नए मकान बनाने की स्वीकृति के दौरान वर्षा के पानी को संरक्षित करने के लिए टांके बनाना जरूरी किया जा रहा है। घरों में नलों से बहते व्यर्थ पानी को भी रोकना होगा। जिले के बांधों में भी वर्षा के जल को रोका जाना चाहिए।

जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियन्ता नरपत सिंह मिर्धा ने स्लाइड प्रदर्शन के जरिए संशोधित जल नीति के मुख्य बिन्दुओं, जिले में जल के परिदृश्य और राज्य में सर्व प्रथम 1999 में बनी जल नीति के दृष्टिकोण तथा गिरते जल भू-जल की स्थिति पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि जिले में 6 बांध विभाग के अधीन है, जबकि 10 बांध ग्राम पंचायतों के अधीन दिए गए हैं। जिले में गत 10 वर्षों में औसत वर्षा 327 मिली मीटर हुई है।

.....2.....

(2)

जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियन्ता आई.डी. खान ने जिले की वर्तमान नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था की विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए बताया कि प्रति वर्ष 3 से 4 फीट पानी नीचे जा रहा है जिसकी वजह से आने वाले समय में आमजन को पानी की समस्या से जुझना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में नगरीय क्षेत्रों में पानी के मीटर लगाए जाएं ताकि उपभोक्ता बिजली की तरह पानी को भी कम खर्च कर सकें। उन्होंने बताया कि अभी भी पानी की मांग और उपलब्धता में काफी अन्तर है, जिसे दूर करने के लिए प्रतिवर्ष नलकूप और हैण्ड पम्प लगाए जा रहे हैं। हर व्यक्ति घर के आगे सोखता गड्ढा बनाए और हर घर में वर्षा के पानी को संरक्षित करने के लिए टांका बनाए जाए। हमें वर्षा के पानी को सहेजकर रखना होगा। जमीन में पानी की सीमित मात्रा को देखते हुए पानी को सभी का बचाने का संकल्प लेना चाहिए।

सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने कार्यशाला विषयक जानकारी देते हुए बताया कि आज की कार्यशाला में दिए

गए सुझावों से राज्य सरकार को अवगत कराया जाएगा ताकि उन पर उचित कार्रवाई हो सके। उन्होंने बताया कि पंचायत समिति स्तर पर भी ऐसी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा और जल संरक्षण में जन प्रतिनिधियों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं का अपेक्षित सहयोग लिया जाएगा। भू-जल विभाग के विशेषज्ञ कुंभाराम ने बताया कि जिले की अलसीसर पंचायत समिति को छोड़कर 7 पंचायत समितियां डार्क जोन में शामिल हैं, जिनमें से चिड़ावा, सूरजगढ़ और बुहाना पंचायत समिति क्षेत्र में नए कुए खोदने व बोरिंग करने पर पूर्णतया प्रतिबन्ध है। उन्होंने बताया कि भू-जल की गुणवत्ता में निरन्तर गिरावट आई है। जल स्रोतों का पुर्नभरण किया जाना जरूरी है।

एक दिवसीय कार्यशाला में कृषि विज्ञान केन्द्र के मुख्य वैज्ञानिक डॉ. एस.एम. मेहता, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जे.एन. मथूरिया ने भी कृषि पैदावार में जल प्रबन्धन की व्यूह रचना और पानी बचाने के तौर तरीकों पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला। जिला परिषद सदस्य रामावतार, मूलचन्द खरींटा, रामेश्वर लाल, जयराम आदि ने अपने-अपने क्षेत्र की पेयजल समस्याओं से अवगत कराते हुए पहाड़ी क्षेत्र में पीने के पानी के तालाब बनाने, पानी की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने, पानी की बचत के लिए हर व्यक्ति की सोच में बदलाव लाने की बात भी कही। राजस्थान पत्रिका के ब्यूरो प्रमुख महेन्द्र सिंह शेखावत ने पेयजल आपूर्ति के दौरान विद्युत कटौती किए जाने व शहर में बूस्टर से पानी खींचने की ओर अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया। आकाशवाणी संवाददाता गोविन्दराम हरितवाल ने खेतड़ी क्षेत्र में पानी की विकट समस्या से अवगत कराते हुए समस्या का हल करने की मांग की। कार्यशाला में जलदाय विभाग के अधिशासी अभियन्ता भरतलाल मीणा ने जिला परिषद सदस्यों द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के बारे में विभागीय जानकारी से अवगत कराया। कार्यशाला में सिंचाई विभाग के सहायक अभियन्ता सुण्डाराम सहित विभागीय अधिकारियों के अलावा स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों एवं जिला परिषद सदस्यों तथा नगर पालिकाओं के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। कार्यशाला का संचालन अलसीसर के सहायक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महेन्द्र सिंह ने किया।

बी.डी.के. अस्पताल को छह ट्रोली व दो डेजर्ट कुलर भेंट

झुंझुनू, 29 जून: जिला मुख्यालय स्थित राजकीय भगवान दास खेतान अस्पताल में दानदाताओं द्वारा रोगियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए संसाधन जुटाने का कार्य अनवरत रूप से जारी है। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. हनुमान सिंह शेखावत ने बताया कि अस्पताल में रोगियों की सुविधा के लिए नवीन मेडिकोज, सांखला ड्रग सेण्टर और मेडिसन सेण्टर द्वारा दो-दो ट्रोली उपलब्ध कराई गई हैं, जबकि समाजसेवी केहर सिंह कटेवा द्वारा दो डेजर्ट कुलर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि आई.सी.यू. वार्ड में सेण्ट्रल आक्सीजन सिस्टम लगाने के लिए भी एक दानदाता द्वारा सहमति प्रदान की गई है।
